डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 जून, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 जून, 2026

| वर्ष 70 | अंक 01 | भोपाल | 1 जून, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

समाज का मूल आधार है सहकारिता : सहकारिता मंत्री श्री सारंग

हस्तशिल्प से आजीविका संवर्धन पर आयोजित संगोष्ठी संपन्न

कढ़ाई एवं जूट शिल्प टूलकिट किये वितरित

सहकारी नवाचार : हस्तशिल्प कारीगरों का सशक्तिकरण कार्यक्रम

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित में हस्तशिल्प क्षेत्र के सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन एवं सहकारी नवाचारों को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग रहे। उनके करकमलों द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सीएचसीडीएस योजना अंतर्गत निर्मित सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी- कॉमन फैसिलिटी सेंटर) भोपाल, इंदौर एवं नौगांव, आधुनिक Coopcraft वाणिज्यिक पोर्टल, CBBO कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का विधिवत लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रारंभ में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक ऋतुराज रंजन ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता एवं सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण एवं बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सहकारी संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि "समाज का मूल आधार सहकारिता है। सहकारिता के माध्यम से परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया संचालित होती है। जब तक एक-दूसरे का समन्वय, सहयोग एवं सहभागिता नहीं होगी, तब तक किसी भी कार्य का सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक टूलकिट के उपयोग से कारीगर अपनी आजीविका को गति दे सकेंगे तथा परिवार की आय में वृद्धि कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कारीगरों से अपील की कि वे इन सुविधाओं एवं प्रशिक्षणों का अधिकतम लाभ लेकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं तथा समृद्ध मध्यप्रदेश एवं विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें।

कार्यक्रम में सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, मनोज पुष्प ने कहा कि सहकारिता मॉडल ग्रामीण विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर एवं डिजिटल विपणन मंचों के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों को उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, डिजाइन विकास एवं विपणन की समेकित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेंगे।

इस अवसर पर श्री वैभव यशवंत मोहारे, उप संचालक हस्तशिल्प, नई दिल्ली एवं अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प कारीगरों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं भविष्य की संभावनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग द्वारा प्रतीक स्वरूप 6 महिला प्रतिभागियों — किरण राजपूत, नीलम यादव, आशा मेहरा, कविता रजक, सोनी यादव एवं महिमा यादव — को कढ़ाई (Embroidery Craft) एवं जूट शिल्प (Jute Craft) से संबंधित आधुनिक टूलकिट वितरित किए गए। इन टूलकिटों के माध्यम से कारीगरों को आधुनिक उत्पादन, गुणवत्ता सुधार एवं स्वरोजगार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में किए गए कार्यों, उपलब्धियों एवं गतिविधियों पर आधारित विशेष पुस्तिका "सहकारिता के नवयुग का शंखनाद" का विमोचन भी किया गया। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास हो रहे फलीभूत : मुख्यमंत्री

दुग्ध उत्पादकों को गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक हुआ भुगतान

प्रतिदिन हो रहा 9.67 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन 11 प्रतिशत हुई वृद्धि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्यों की समीक्षा की

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। समन्वित प्रयासों से मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन बढ़ाते हुए लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की उपलब्धि दर्ज हुई है। यह गत वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि को निरंतर बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में पशुपालन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि गत छह माह में 11 लाख किलोग्राम से अधिक औसत प्रतिदिन दुग्ध संकलन हुआ है। दुग्ध संघों ने दुग्ध उत्पादक किसानों को गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान किया है। पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनू योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, मवेशियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख,चारा उत्पादन और उपलब्धता,पशु पोषण,स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना, क्षीरधारा ग्राम योजना,ब्रीडर एसोसिएशन,दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, गोरस ऐप, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यों और एनडीडीबी द्वारा दिए जा रहे सहयोग की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की।

दुग्ध उत्पादन में नम्बर वन बनाना है प्रदेश को

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे क्रम पर है। हमारा लक्ष्य प्रथम क्रम पर आने का है। इस दिशा में प्रारंभ किए गए प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। ग्वालियर डेयरी प्लांट के आधुनिकीकरण, शिवपुरी डेयरी प्लांट को पुनर्जीवन देने, इंदौर में 3 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले मिल्क पाउडर प्लांट की शुरूआत जैसे ठोस कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही इन प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध उत्पादन और विक्रय के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहयोग मिला है। ये प्रयास जारी रहना चाहिए।

बीते वर्ष दुग्ध उत्पादकों को किया 1609 करोड़ रूपये का भुगतान

प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में हुए कार्यों से वर्ष 2024-25 में 1398 करोड़ की तुलना में वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 1609 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान (गत वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक) में सफलता मिली है। दुग्ध उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली से विभिन्न दुग्ध संघों में खरीद मूल्य में 2.50 से 8.50 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। किसानों की आय बढ़ने से उनके जीवन में समृद्धि आ रही है।

सांची ब्रांड को सुदृढ़ करने में मिली कामयाबी

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में विपणन और ब्रांड सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत सांची ब्रांड को लोकप्रिय बनाते हुए विभिन्न उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में भी सफलता मिली है। मूल्यसंवर्धित उत्पादों में घी की बिक्री 17प्रतिशत बढ़ी है। पनीर, दही, छाछ और फ्लेवर्ड दूध की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज हुई है। बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के प्रयास भी किए गए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

30 जून तक चलाये पैक्स का सदस्यता अभियान : डॉ. यादव

अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी बैंक होंगे सुदृढ़

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन पूर्ण; जल्द ही मोबाहल ऐप पर ट्रांजेक्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में नवीन सदस्य बनने के लिए सदस्यता अभियान 30 जून तक चलाएं। गत 14 अप्रैल से शुरू सदस्यता अभियान के जरिए पैक्स में 10 लाख नवीन सदस्य जोड़ें। उन्होंने कहा कि वर्ष में सवा लाख नए केसीसी स्वीकृति का लक्ष्य रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सुदृढ़ीकरण की सराहना करते हुए कहा है कि अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का सुदृढ़ीकरण किया जाए। बताया गया कि गत ढाई वर्षों में 18 कमजोर जिला बैंकों में से 6 की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शासकीय अंश पूंजी सहायता से 6 जिला बैंक रीवा, सतना, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर एवं दतिया को सुदृढ़ करने का प्रयास है। अगले चरण में अन्य 6 भिंड, मुरैना, रायसेन, सागर, सीधी और नर्मदापुरम बैंक के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पैक्स से लेन-देन की प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के जरिए किए जाने के प्रयास किए जाएं। इस पर बताया गया कि प्रदेश की सभी 4536 पैक्स को केंद्र प्रायोजित कंप्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत कंप्यूटरीकृत कराया गया है। शत-प्रतिशत कंप्यूटराइजेशन से योजना क्रियान्वयन में प्रदेश देश में अग्रणी है। जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजेक्शन भी किया जा सकेगा।

बैठक में बताया गया की बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गत 2 वर्षों में 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं विपणन हुआ है। 1102 नई दुग्ध समितियों का गठन कर 5562 दुग्ध समितियों तथा वित्तीय समावेशन के लिए 76 हजार सदस्यों के खाते जिला सहकारी बैंक में खोले गए हैं। व्यापक स्तर पर भर्ती एवं संस्थागत क्षमता निर्माण के प्रयास किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के साथ भागीदारी एवं व्यवसाय

बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर की नवीन गठित तीन सहकारी समितियों के साथ भागीदारी एवं व्यवसाय किया गया है।भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (BBSSL) के साथ प्रदेश के सहकारी बीज संघ ने MoU किया है जिससे 17 करोड़ रूपये का व्यवसाय और 844 पैक्स द्वारा सदस्यता प्राप्त हुई है।राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लि. (NCOL) के साथ प्रदेश के सहकारी विपणन संघ का MoU हुआ जिससे 1335 पैक्स द्वारा सदस्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (NCEL) और प्रदेश के सहकारी संघ के साथ MoU में 1612 पैक्स द्वारा सदस्यता प्राप्त हुई। अभी उत्पादों का चिन्हांकन प्रक्रियाधीन है।

पारंपरिक मछली पालन से आगे बढ़कर स्टार्टअप आधारित होगा मत्स्योद्योग : राज्यमंत्री

मध्यप्रदेश बनेगा देश का ब्लू इकॉनमी हब: केज कल्चर के लिए डेढ़ से दो लाख प्रस्ताव

निवेशकों के लिए नियुक्त होंगे कॉन्टैक्ट ऑफिसर, योजना, सब्सिडी और दस्तावेजीकरण में करेंगे मदद

कोल्ड चेन, हैचरी और फिश फीड पर मिलेगी सब्सिडी: कृषि उत्पादन आयुक्त श्री बर्णवाल

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मत्स्योत्पादन को दोगुना करने के विजन को लेकर 'मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026' के सफल क्रियान्वयन की दिशा में राज्य स्तरीय 'हितधारक सम्मेलन' हुआ। इस सम्मेलन में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार की उपस्थिति में मत्स्य क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों ने उत्साह दिखाया।

राज्यमंत्री श्री पंवार ने कहा कि प्रदेश में पहले वर्ष 10 हज़ार केज लगाने का लक्ष्य था, लेकिन निवेशकों की ओर से लगभग 2 लाख केज लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। यह दिखाता है कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने की दिशा में विभाग द्वारा सकारात्मक पहल की जा रही है।

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार ने कहा कि आज का यह समागम केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार पहली बार पारंपरिक मत्स्य पालन की सीमाओं से आगे बढ़कर एकीकृत मत्स्योद्योग (हितग्राही और उद्यमी मॉडल) पर काम कर रही है। इसे केवल एक समाज आधारित योजना के रूप में न देखकर, हर वर्ग को साथ लेकर चलने और रोजगार सृजन की 'स्टार्टअप आधारित ब्लू इकॉनमी' के रूप में देखा जाना चाहिए।

केज कल्चर के लिए खत्म हो आवेदन की समय सीमा: श्री पंवार

राज्यमंत्री श्री पंवार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केज कल्चर के प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया को किसी समय-सीमा में न बांधा जाए। इसे एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक युवा उद्यमी और हितग्राही इससे जुड़ सकें। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव मत्स्य विकास के लिए 100 करोड़ रुपये तक खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने, हैचरी निर्माण और फिश फीड के लिए शासन द्वारा पूरी सहायता और सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बैंकिंग और इंश्योरेंस क्षेत्र के हितधारकों से मत्स्य उत्पादन के आधुनिकीकरण में सहयोग की अपील की।

हर निवेशक के साथ जुड़ेंगे कॉन्टैक्ट ऑफिसर: सचिव श्री सिंह

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश जलाशयों का केंद्र है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए हर निवेशक के साथ सुविधानुसार एक 'कॉन्टैक्ट ऑफिसर' नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी निवेशक के सभी आवश्यक दस्तावेजीकरण, सब्सिडी और अन्य विभागीय कार्यों को पूर्ण कराने में मदद करेगा। साथ ही, विभाग द्वारा मार्केटिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े एक्सपर्ट्स की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह पंवार ने केज कल्चर के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक रूप से चयनित केज कल्चर के हितधारकों को अभिस्वीकृति पत्र वितरित किये गए। मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक श्री अनुराग चौधरी ने सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में निवेशकों और उद्यमियों के साथ 'राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस' भी आयोजित की गई, जिसमें स्टेक होल्डर्स से प्राप्त प्रस्तावों और अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा, प्रदेश में 'केज कल्चर' को बढ़ावा देने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले सीड, फीड और जाल आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विक्रेताओं के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के संचालक श्री मनोज पथरोलिया, मत्स्य महासंघ के महाप्रबंधक श्री रवि गजभिए समेत प्रदेश भर से आए मत्स्य उद्यमी, निवेशक, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। उप संचालक, मत्स्योद्योग श्री गिरीश मेश्राम ने सभी अतिथियों, निवेशकों और हितधारकों के प्रति आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

उपभोक्ता हित में अन्य विभागों से समन्वय बढ़ाकर कार्य करे खाद्य विभाग : मुख्यमंत्री

अनाजों के भंडारण में क्षति कम करने भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई में प्रशिक्षण की पहल

मंत्रालय में हुई खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य विभाग अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित कर उपभोक्ता हित में कार्य करे। खाद्य विभाग ने अनेक नवाचार किए हैं जिनका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। नवाचारों और उपभोक्ता हित का कार्य निरंतर किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण मार्ट के रूप में उन्नयन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मोबाइल पर संदेश भेजकर राशन प्रदाय और वितरण की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। यह नवाचार उपभोक्ताओं के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ता के रूट ऑप्टिमाइजेशन के कार्य से परिवहन लागत में सरकार को 42 लाख रुपए प्रति माह की बचत हुई। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल कमांड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग व्यवस्था की गई। इसी तरह सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने सभी स्तरों पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने गोदाम में स्कंध के भंडारण की क्षति को कम करने के लिए वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अमले को भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई में प्रशिक्षण दिलवाने की पहल की भी प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निगम कर्मियों के कौशल उन्नयन की गतिविधियां जारी रखी जाएं।इसी तरह उपार्जन, मिलिंग और परिवहन के लिए उपयोग में लिए जा रहे वाहनों का यूलिप (ULIP) सॉफ्टवेयर से सत्यापन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर से खाली बारदाने क्रय करने के लिए सीसी लिमिट से भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था लागू करने वाला मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के पश्चात तीसरा प्रांत है। इस प्रणाली से 18 करोड़ रुपए की ब्याज राशि की बचत करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गेहूं उपार्जन कार्य की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ऐसा मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए जिससे गेहूं की जींस की प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग आदि के कार्य लघु मध्यम और सूक्ष्म विभाग के सहयोग से किए जा सकें। इस कार्य में स्व-सहायता समूह की भूमिका भी हो सकती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शहरी गैस वितरण, नेटवर्क विकास और विस्तार नीति 2025 लागू करने, पीडीएस के हितग्राहियों का ई-केवाईसी किए जाने के कार्य और उपभोक्ता हित में किए गए अन्य प्रयासों की जानकारी भी प्रदान की गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अगले पांच साल तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

लाखों किसानों को मिलेगा लाभ ● प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कैबिनेट ने स्वीकृत किये 11608.47 करोड़

भोपाल : किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश के किसानों को बडा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11608.47 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता देने योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन, फसल स्थिति और उपज निर्धारण में तकनीकी के उपयोग में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है।

वर्ष 2023-24 में 35.18 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 961.68 करोड़ का दावा भुगतान किया गया। वर्ष 2024-25 में 35.56 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 275.86 करोड़ का दावा भुगतान किया गया।

प्रदेश में वर्ष 2016 से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में भागीदार किसानों को फसल नुकसान या क्षति होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा देय होता है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमांकित प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिसडी की दर माना जाता है। इसकी भागीदारी केन्द्र और

राज्य द्वारा बराबर वहन की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा सिंचित और असिंचित जिलों की फसलों में केन्द्र सरकार की प्रीमियम सब्सि डी की सीलिंग क्रमश: 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक रखी गई है। यदि इस सीलिंग के अधिक दरें प्राप्त होती हैं तो अतिरिक्त भार राज्य शासन को वहन करना होता है। मध्यप्रदेश में क्षतिपूर्ति् स्तर का 80 प्रतिशत निर्धारित है। आगामी वर्षो में भी सभी फसलों के लिये क्षतिपूर्ति का स्तर 80 प्रतिशत रखा गया है।

वैकल्पिक क्रियान्वयन मॉडल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मॉडल चुन सकता है।

पहला कप एण्ड सरप्लस शेयरिंग 80-110 मॉडल और दूसरा कप एण्ड केप सरप्लस शेयरिंग 60-130 मॉडल। कप एण्ड केप सरप्लस शेयरिंग 80-110 मॉडल के अंतर्गत कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत तक का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है। 110 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त क्लेम राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। 80 प्रतिशत से कम क्लेम बनने पर क्लेम एवं 80 प्रतिशत के अंतर की सरप्लस राशि बीमा कम्पनी द्वारा राज्य शासन को वापस की जाती है।

कप एण्ड केप सरप्लस शेयरिंग 60-130 मॉडल के अंतर्गत कुल प्रीमियम के 130 प्रतिशत तक का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है। 130 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त क्लेम राशि का वहन राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर अनुपात में किया जाता है। 60 प्रतिशत से कम क्लेम बनने पर क्लेम एवं 60 प्रतिशत के अंतर की सरप्लस राशि बीमा कम्पनी द्वारा राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार को वापस की जाती है। मॉडल पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर लिया जायेगा।

किसानों को फायदें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होने पर किसानों को मदद करती है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है। छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना 2 प्रतिशत (खरीफ फसलें), 1.5 प्रतिशत (रबी फसलें) और 5 प्रतिशत (वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें) की प्रीमियम दर पर किसानों के व्यय को कम करने और किसानों की आय को स्थिर करने के उद्देश्य से फसल विफलता होने पर एक व्यापक बीमा कवर देती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के जिलों में 11 क्लस्टर्स में किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर के लिये बीमा कंपनियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है।

फसल उपज का आंकलन सेटेलाईट आधारित रिमोट सेसिंग तकनीक से किया जा रहा है। इसके लिये कृषि विभाग द्वारा नेशनल रिमोट सेसिंग केन्द्र (इसरो), मध्यप्रदेश काउसिंल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से समझौता किया गया है। मौसम सूचना तंत्र एवं डाटा प्रणाली का उपयोग कर योजना का क्रि यान्वयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल को मिला सिक्योरिटी गार्ड प्रशिक्षण केंद्र संचालन का लाइसेंस

युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा Private Security Agencies Regulation Act (PSARA), 2005 एवं मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2012 के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर एवं डायरेक्टर प्रशिक्षण केंद्र संचालन हेतु अधिकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है।यह लाइसेंस दिनांक 26 मई 2026 से 25 मई 2031 तक के लिए वैध रहेगा। प्रशिक्षण केंद्र का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा शाहपुरा स्थित प्रशिक्षण केंद्र से किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से अब प्रदेश के युवाओं को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी, सुरक्षा प्रबंधन एवं रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इससे ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को निजी सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल लंबे समय से सहकारिता, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अब सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से संस्था एक नए आयाम की ओर अग्रसर हुई है।संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक तकनीकों, व्यवहारिक अभ्यास एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे प्रशिक्षित युवाओं को निजी सुरक्षा एजेंसियों, औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक परिसरों, बैंकिंग संस्थाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।इस अवसर पर संस्था से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसे मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की एक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पहल युवाओं के कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी।

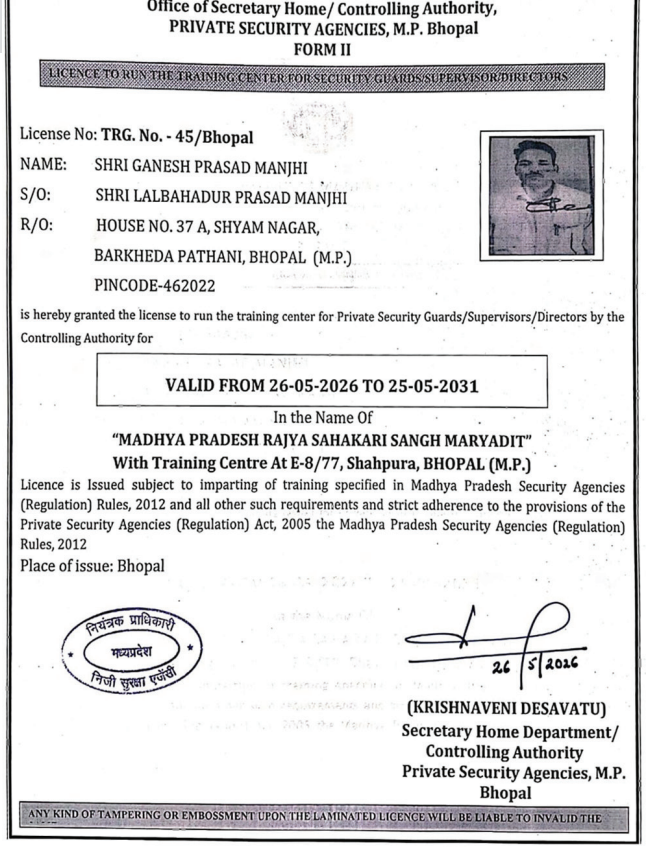

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
Office of Secretary Home/ Controlling Authority,
PRIVATE SECURITY AGENCIES, M.P. Bhopal
FORM II

LICENCE TO RUN THE TRAINING CENTER FOR SECURITY GUARDS/SUPERVISOR/DIRECTORS

License No: **TRG. No. - 45/Bhopal**

NAME: SHRI GANESH PRASAD MANJHI
S/O: SHRI LALBAHADUR PRASAD MANJHI
R/O: HOUSE NO. 37 A, SHYAM NAGAR,
BARKHEDA PATHANI, BHOPAL (M.P.)
PINCODE-462022

is hereby granted the license to run the training center for Private Security Guards/Supervisors/Directors by the Controlling Authority for

VALID FROM 26-05-2026 TO 25-05-2031

In the Name Of
"MADHYA PRADESH RAJYA SAHAKARI SANGH MARYADIT"
With Training Centre At E-8/77, Shahpura, BHOPAL (M.P.)

Licence is Issued subject to imparting of training specified in Madhya Pradesh Security Agencies (Regulation) Rules, 2012 and all other such requirements and strict adherence to the provisions of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 the Madhya Pradesh Security Agencies (Regulation) Rules, 2012

Place of issue: Bhopal

निरंत्रक प्राधिकारी मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा एजेंसी

26/5/2026

(KRISHNAVENI DESAVATU)
Secretary Home Department/
Controlling Authority
Private Security Agencies, M.P.
Bhopal

ANY KIND OF TAMPERING OR EMBOSSMENT UPON THE LAMINATED LICENCE WILL BE LIABLE TO INVALID THE

उपार्जन से कोई किसान न छूटे, सभी किसानों का पात्रता अनुसार गेहूँ क्रय किया जाए

वन भूमि एवं शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटें

अवैध माइनिंग पर अंकुश लगाया जाए प्रभारी मंत्री करेंगे औचक निरीक्षण

आगामी वर्ष से ग्राम पंचायत स्तर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की तैयारी : मंत्री श्री सारंग

हरदा जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक

भोपाल :हरदा जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के जिले में सुव्यवस्थित इंतजाम रहें। कोई भी पात्र किसान गेहूँ बेचने से न छूटे। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को असुविधा न हो। जिले में उपार्जन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर किसानों को आश्वस्त किया जाए कि उनके गेहूँ की खरीदी अवश्य होगी। मंत्री श्री सारंग सोमवार को हरदा जिला कलेक्ट्रेट में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, विधायक डॉ. आर.के. दोगने, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, पूर्व विधायक टिमरनी श्री संजय शाह सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।

मंत्री श्री सारंग ने जिले में आगामी सीजन में सुगमता से उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आगामी वर्ष से ग्राम पंचायत स्तर पर भी उर्वरक वितरण करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि जिले में कहीं भी खनिज का अवैध उत्खनन अथवा परिवहन न हो। खनिज का अवैध धंधा करने वालों में पुलिस का खौफ रहे। वे स्वयं इसका औचक निरीक्षण करेंगे। आगामी दो माह में वनभूमि से समस्त अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा शासकीय भूमि से आगामी तीन माह में सभी तरीके के अतिक्रमण हटाने के लिये अधिकारियों को पाबंद किया गया। श्री सारंग ने बैठक में विद्युत की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिये गये। साथ ही पशुपालन विभाग को जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं नई समितियों का गठन करने के लिये निर्देशित किया गया। जल संसाधन विभाग अंतर्गत मूंग की फसल में सिंचाई के पानी की आपूर्ति की जानकारी ली गई। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि परीक्षा परिणामों में अपेक्षित सुधार लाया जाए। सांदीपनी स्कूलों के प्रारंभ होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव का अध्ययन किया जाए। उन्होने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों के अनियमित उपस्थिति के कारणों का भी विश्लेषण किया जाए। मंत्री ने निर्देश दिये कि सार्वजनिक अधोसंरचनाओं के लिये सुगम पहुँच मार्ग उपलब्ध रहें, यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि विधायक एवं सांसद निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गये पानी के टैंकर ग्राम पंचायतों में ही खड़े हो, इस बात का भौतिक सत्यापन किया जाए।

सड़क निर्माण से संबंधित विभागों को प्रत्येक सड़क पर सड़क निर्माण का वर्ष, गारंटी की अवधि एवं ठेकेदार का नाम व मोबाइल नम्बर अंकित करने के निर्देश दिये गये। मण्डी निधि से निर्माणाधीन सड़कों में आ रही अड़चनों को चिन्हित कर हल करने के निर्देश दिये गये। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत स्कूल प्रारम्भ होने के पूर्व छात्रावासों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिये भी विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की आपूर्ति सुचारू रहे। समस्यामूलक गांवों में पानी की समस्या हल करें। सड़क निर्माण से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि जो सड़कें खराब हो गई है, उनके उन्नयन के प्रस्ताव तैयार किये जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। गारंटी अवधि में सड़कों का संधारण नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार की नियमानुसार राशि राजसात की जाए। जो सड़के गारंटी से बाहर हो गई है, उनके उन्नयन के प्रस्ताव तैयार किये जाएं। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिले में राशन वितरण से संबंधित उपभोक्ताओं को शिकायत न हो। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग को जिले के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरूस्त रखने के लिये भी निर्देशित किया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश के किसान इन सभी प्रावधानों का लाभ प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत अनेक गतिविधियों आयोजित की जा रही हैं। प्रत्येक माह किसानों के कल्याण के लिए उन्नत यंत्रों की प्रदर्शनियां, किसान हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही किसानों को नई कृषि तकनीक के प्रशिक्षण का लाभ दिलवाया जा रहा

है। केंद्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनत समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने से मध्यप्रदेश और देश के किसान प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश श्री अन्न उत्पादन में आगे है। इस नाते प्रदेश के रागी, मक्का,ज्वार और बाजरा उत्पादक किसानों को इस फैसले से विशेष लाभ होगा।

विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि

केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल, नाइजर सीड में 515 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। उत्पादन लागत पर किसानों को अनाजों में सर्वाधिक मूंग में सबसे अधिक 61 प्रतिशत लाभ रहने का अनुमान है। इसके बाद बाजरा और मक्का में 56 प्रतिशत और अरहर में 54 प्रतिशत लाभ का अनुमान है। जहां उड़द में यह प्रतिशत 51 है, वहीं रागी, हाइब्रिड ज्वार और धान में लागत पर 50 प्रतिशत लाभ किसानों को मिलेगा। तिलहन फसलों में मूंगफली, सूरज मुखी के बीज, तिली सोयाबीन, तिल,नायजर सीड और मध्यम रेशे के कपास में किसानों को लागत पर मार्जिन 50-50 प्रतिशत का अनुमान है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाज का मूल आधार है सहकारिता .....

कार्यक्रम के दौरान माननीय सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नवस्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण करते हुए वहां स्थापित आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने केन्द्र में कार्य कर रही महिला कारीगरों से संवाद कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य, उत्पादन प्रक्रिया, प्रशिक्षण एवं मशीनों के उपयोग की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री सारंग ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हस्तशिल्प उत्पादों की सराहना करते हुए उन्हें गुणवत्ता, नवाचार एवं बाजार की मांग के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने कारीगरों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास, उत्पादों के विपणन, डिजाइन नवाचार एवं स्वरोजगार के नए अवसरों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक एवं प्रशिक्षण के माध्यम से हस्तशिल्प क्षेत्र को नई पहचान दिलाई जा सकती है तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में शुभारंभ किए गए Coop-craft पोर्टल को हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक आधुनिक डिजिटल बाजार एवं सूचना मंच के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कारीगर अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रदर्शन, विपणन, ग्राहक संपर्क एवं व्यावसायिक विस्तार कर सकेंगे। यह पहल "लोकल टू ग्लोबल" की अवधारणा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, कारीगरों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में सहकारिता आधारित विकास मॉडल को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया।

अपेक्स बैंक के प्रशासक ने इंदौर संभाग के पांच जिला सहकारी बैंकों की वर्चुअल बैठक लेकर दिए महत्वपूर्ण निर्देश

भोपाल। किसानों को सहकारिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा राज्य शासन द्वारा घोषित "किसान वर्ष-2026" को सफल बनाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने इंदौर संभाग के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों - इंदौर, धार, खंडवा, झाबुआ एवं खरगोन - के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा वर्ष 2026 को "किसान वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सहकारी बैंकों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को समितियों का सदस्य बनाया जाए तथा उन्हें अंश पूंजी जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि किसान सहकारिता आंदोलन से जुड़कर विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों की समितियों की नियमित समीक्षा करें तथा गांवों का सतत प्रवास कर किसानों से सीधा संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को सरल एवं सहज भाषा में सहकारी बैंकों की योजनाओं, ऋण सुविधाओं, फसल वित्तपोषण, बीज एवं खाद वितरण तथा अन्य सेवाओं की जानकारी दी जाए, ताकि किसान इन सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।

बैठक में प्रशासक श्री यादव ने राशन दुकानों से संबंधित प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने विक्रय एवं उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा कृषि विस्तार अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर खाद-बीज वितरण व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को तुलाई एवं खरीदी में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सकारात्मक एवं पारदर्शी वातावरण तैयार करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बैठक के प्रारंभ में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने 14 अप्रैल से प्रारंभ विशेष सदस्यता अभियान, वसूली अभियान, खरीफ फसल ऋण वितरण, प्रति पैक्स एवं प्रति शाखा टर्म लोन वितरण, पैक्स में बहुउद्देशीय गतिविधियों के संचालन, अमानतों में वृद्धि तथा गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संभागीय शाखा प्रबंधकों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रशासक महोदय की मंशा एवं सहकारिता विभाग की प्राथमिकताओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में ऋण वितरण एवं वित्तीय गतिविधियों के संबंध में उप महाप्रबंधक के टी सज्जन ने भी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अरुणा दुबे, अरुण मिश्रा, अरविंद बौद्ध, आर के गंगेले तथा जनसंपर्क अधिकारी अभय प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में "रिफॉर्म एक्सप्रेस" पर सवार है कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय- श्री शिवराज सिंह चौहान

दिल्ली| प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले ही दिन अपने दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर साफ कहा कि सरकार का काम फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान, गरीब, ग्रामीण और आम नागरिक को योजनाओं का लाभ पाने या शिकायतों के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए योजनाबद्ध, समयबद्ध और परिणाममुखी व्यवस्था तुरंत खड़ी की जाए। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम आदमी को लड़ना न पड़े, उसे दर-दर भटकना न पड़े और उसे योजनाओं का लाभ सहज, सरल और समय पर मिलना चाहिए। इसी को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और आईसीएआर समेत संबंधित इकाइयों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभी विभिन्न योजनाओं और विभागों में शिकायतों के निपटारे की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे अलग पोर्टल, अलग तंत्र और अलग प्रणाली, लेकिन अब इस व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी और परिणामकारी बनाने की जरूरत है। इसके लिए कृषि और ग्रामीण विकास, दोनों विभागों में कम से कम 10-10 अधिकारियों की टीम गठित करने को कहा गया, जो प्रतिदिन शिकायतों, जनसमस्याओं, पत्रों, जनप्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों और विभिन्न पोर्टलों पर आई समस्याओं की समीक्षा करे।

श्री चौहान ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिकायतों का समाधान केवल कागज पर "डिस्पोजल" दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह देखा जाए कि लाभार्थी को वास्तविक राहत मिली या नहीं, योजना का लाभ वास्तव में पहुंचा या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड में वितरण दिख रहा हो लेकिन जमीन पर लाभार्थी को कुछ मिला ही न हो। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने अपने उस अनुभव का भी उल्लेख किया, जिसमें लाभार्थियों को फोन कर सत्यापन करने पर कुछ मामलों में कागज और वास्तविकता के बीच अंतर सामने आया था। उन्होंने साफ कहा कि यह समस्या आसान नहीं, बल्कि जटिल है, इसलिए शिकायतों की प्रकृति, क्षेत्रवार प्रवृत्ति और योजनावार अड़चनों की पहचान कर तंत्र में आवश्यक बदलाव करना होगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि हर महीने शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि महीने के पहले सोमवार को समीक्षा की जाएगी, हालांकि जून में खरीफ कार्यों की व्यस्तता को देखते हुए दूसरे सोमवार को विस्तृत समीक्षा की जाएगी, लेकिन तब तक तंत्र और अधिक व्यवस्थित, उत्तरदायी और प्रभावी हो जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफॉर्म्स पर दिए जा रहे लगातार जोर का उल्लेख करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब हर डिवीजन, हर योजना और हर विभाग अपने स्तर पर यह पहचाने कि आखिर कठिनाई कहां है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क योजना, कृषि योजनाएं, बागवानी, बीमा, विपणन या अन्य कार्यक्रमों में जहां कहीं लाभार्थी बेवजह चक्कर काट रहा है, वहां नियम, प्रक्रिया, तंत्र और कार्यप्रणाली को सरल बनाना ही होगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने साफ कहा कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए और पुराने-अप्रासंगिक रेगुलेशंस को खत्म करना अब जरूरी है। उन्होंने पूछा कि हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत क्यों हो, कई जगह पंजीकरण या आसान प्रणाली से काम क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर विभिन्न योजनाओं में बाधा पैदा करने वाले प्रावधानों, जटिल प्रक्रियाओं और सुधार योग्य बिंदुओं की पहचान कर ली जाए, ताकि आगे त्वरित निर्णय लिया जा सके। बैठक में एआई और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर महत्वपूर्ण रूप से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और आईसीएआर सहित सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा शेयरिंग, डेटा आधारित निर्णय, मॉनिटरिंग और इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय को और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए अलग टीम बनाकर अध्ययन करने और उपयोगी प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए विभागों के बीच साझा कामकाज और डेटा इंटीग्रेशन जरूरी है। बैठक में यह भी सामने आया कि विभिन्न शिकायत डेटाबेस को जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है, ताकि केवल एक पोर्टल की नहीं बल्कि समेकित शिकायत-प्रणाली के आधार पर विभागीय मूल्यांकन हो सके।

श्री चौहान ने प्रशासनिक कार्य संस्कृति में बदलाव पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि फाइल नीचे से बनकर ऊपर आती है और कई बार नीचे का पुराना माइंडसेट ही पूरी प्रक्रिया को उलझा देता है। इसलिए केवल ऊपर के स्तर पर नहीं, बल्कि नीचे से फाइल निर्माण, नोटिंग, निर्णय-तैयारी और ड्राफ्टिंग की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है। उन्होंने ड्राफ्टिंग को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि विभागों में ऐसे अधिकारी विकसित किए जाएं जो फाइलें और नोट्स मजबूत, स्पष्ट और नीति-संगत तरीके से तैयार कर सकें। इसके लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और दक्षता वृद्धि की व्यवस्था की जाए, ताकि फाइलें अनावश्यक रूप से न अटकें और निर्णय की गुणवत्ता भी बेहतर हो।

न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में सरकार इसलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि सरकारी पक्ष समय पर और प्रभावी ढंग से अदालत में रखा ही नहीं जाता। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि वे लंबित कोर्ट केसों की सूची निकालें, उनकी समीक्षा करें, नोडल अधिकारी तय करें, विधिक तैयारी मजबूत करें और जरूरत पड़े तो बेहतर वकीलों की व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार की हार का सीधा नुकसान सार्वजनिक हित को होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास कार्यों में बाधाओं की पहचान और समाधान पर दिए गए संदेश को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर डिवीजन यह बताए कि काम किस वजह से अटकता है, कौन सी बाधाएं फैसलों, क्रियान्वयन और लाभ वितरण में देरी करती हैं, और उन्हें दूर करने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कवायद एक साथ चलनी चाहिए- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ-साथ इन्फॉर्म भी।

उन्होंने कहा कि कई बार योजनाएं अच्छी होती हैं, सुधार भी किए जाते हैं, लेकिन जनता को जानकारी ही नहीं होती। इसलिए हितधारकों से संवाद, किसान संगठनों के साथ बैठक, मजदूरों और सरपंचों से बातचीत, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, वीडियो, रील्स और रचनात्मक संचार माध्यमों से योजनाओं और सुधारों को जनता तक पहुंचाया जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि जो सुधार पहले ही किए जा चुके हैं, उनका "रिफॉर्म उत्सव" की तरह प्रचार-प्रसार होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि केवल सुधार कर देना काफी नहीं है, बल्कि जिनके लिए सुधार किए गए हैं, उन्हें बुलाकर संवाद किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि क्या बदला है, उससे क्या लाभ होगा और आगे क्या और किया जा सकता है।

श्री चौहान ने राज्यों के साथ साझेदारी को कृषि और ग्रामीण विकास की सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि असली काम राज्यों में होता है, इसलिए राज्यों के साथ रोडमैप आधारित साझेदारी, ज़ोनल कॉन्फ्रेंस, योजनावार समन्वय और समस्या-आधारित संवाद को और मजबूत किया जाए। उन्होंने संकेत दिया कि जो राज्य संकोच करते हैं, उनके साथ भी संवाद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि केंद्र का दायित्व पूरे देश की जनता के प्रति है। उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की भी जरूरत बताई। उनका कहना था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और क्षेत्रीय कृषि रोडमैप जैसे मुद्दों पर अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को साथ बैठकर काम करना होगा।

बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप विभागीय विजन दस्तावेज तैयार करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपना 2047 विजन, इस वर्ष के लक्ष्य, वार्षिक, छह-माही, तिमाही, साप्ताहिक और दैनिक कार्ययोजना तैयार करे, ताकि मॉनिटरिंग मजबूत हो और काम का आकलन स्पष्ट रूप से हो सके। उन्होंने सरकारी भवनों और संस्थानों में पीएम सूर्य घर जैसी पहलों के अनुरूप सोलराइजेशन को भी आगे बढ़ाने की बात कही और कहा कि जहां काम हो चुका है और जहां बाकी है, उसका स्पष्ट आकलन तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा कार्यकाल के दो वर्ष और समग्र 12 वर्षों की उपलब्धियों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण पर भी बैठक में चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि विभाग अपनी उपलब्धियों को अभी से व्यवस्थित करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही गांव स्तर तक जाने वाले कार्यक्रम, प्रेजेंटेशन, रचनात्मक कंटेंट, वीडियो और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए छोटे वीडियो, ग्राफिक्स, लाभार्थी कहानियों और योजनाओं से जीवन में आए बदलावों को केंद्र में रखने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि अखबार और टीवी के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दमदार प्रस्तुतीकरण आज ज्यादा असरकारी हो सकता है। बैठक में विदेश यात्राओं को लेकर भी प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देशों का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचा जाए और केवल अत्यंत जरूरी मामलों में ही ऐसे प्रस्ताव आगे आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय प्राथमिकता देश के भीतर काम की गति, गुणवत्ता और परिणाम को बेहतर बनाना है। फाइलों के निस्तारण को लेकर श्री चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल तेजी नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और परिणाममूलक निर्णय है। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम या फाइल कई लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है, इसलिए उसे समझकर, परखकर और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे अनावश्यक देरी न हो और महत्वपूर्ण मामलों पर समय रहते चर्चा हो सके।

बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी विभाग पीछे नहीं रहना चाहिए। शिकायत निवारण से लेकर रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, कोर्ट केस, राज्यों से समन्वय, जनसंवाद, 2047 रोडमैप और उपलब्धियों के प्रस्तुतीकरण तक हर मोर्चे पर सक्रिय, समयबद्ध और जवाबदेह कार्यशैली अपनानी होगी, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुशासन विजन के अनुरूप सरकार का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

सीएचसीडीएस योजना अंतर्गत हस्तशिल्पियों हेतु एक दिवसीय सेमिनार आयोजित

भोपाल। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित "सीएचसीडीएस (CHCDS) क्लस्टर विकास योजना" अंतर्गत प्रदेश के हस्तशिल्प कारीगरों के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को कौशल उन्नयन, स्वरोजगार, विपणन, वित्तीय प्रबंधन एवं आधुनिक व्यवसायिक जानकारी प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना रहा।

कार्यक्रम में हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों द्वारा हस्तशिल्पियों को बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंधन, जीएसटी, व्यवसाय विकास, विपणन रणनीति, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिज़ाइन विकास, उत्पाद गुणवत्ता सुधार एवं हस्तशिल्प कला के संरक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर श्री वैभव यशवंत मोहारे, उप संचालक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत सरकार हस्तशिल्प कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

श्री नरसिंह सैनी, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, भोपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र भारतीय संस्कृति एवं परंपरा की पहचान है तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के माध्यम से कारीगरों को नए बाजार अवसरों से जोड़ा जा रहा है।

कार्यक्रम में श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल ने कहा कि हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा सहकारिता के माध्यम से कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें हस्तशिल्पियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा व्यवसाय से संबंधित समस्याओं एवं संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें व्यवसाय विस्तार, डिजिटल विपणन, उत्पाद गुणवत्ता सुधार एवं स्वरोजगार से संबंधित व्यावहारिक सुझाव दिए गए।

उपार्जन केन्द्र गौरी वेयरहाउस पहुँचे अपेक्स बैंक के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्वालियर की शाखा पिछोर एवं डबरा अंतर्गत संचालित समितियों — पिछोर तथा डबरागांव का सघन दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उपार्जन केन्द्र गौरी वेयरहाउस पहुंचकर उपार्जन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर बैंकिंग सेवाओं, फसल ऋण एवं खाद वितरण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान प्रशासक श्री यादव ने उपार्जन केन्द्र पर तुलाई, भंडारण, किसानों की सुविधा, खाद उपलब्धता एवं फसल खरीदी व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को उपार्जन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने किसानों से चर्चा करते हुए फसल ऋण वितरण, ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था एवं खाद

की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। किसानों ने भी उपार्जन केन्द्र की व्यवस्थाओं एवं बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में अपने सुझाव साझा किए। प्रशासक श्री यादव ने किसानों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

दौरे के दौरान बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं सदस्यता अभियान के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित "नुक्कड़ नाटक" का भी अवलोकन किया गया। इस रचनात्मक पहल की सराहना करते हुए श्री यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता की योजनाओं को आम किसानों तक सरल भाषा एवं सांस्कृतिक माध्यमों से पहुंचाना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा घोषित "किसान कल्याण वर्ष-2026" के अंतर्गत संचालित सदस्यता महाअभियान की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशासक श्री यादव ने दोनों समितियों में नवीन सदस्य बनाए जाने की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए। दौरे के दौरान विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अभय प्रधान, बैंक के प्रबंधक (प्रशासन) अभिषेक प्रकाश झा, कार्यालय अधीक्षक श्रीपाल सिंह यादव, विपणन अधिकारी गोपाल सिंह परिहार, पिछोर शाखा प्रबंधक भूपेन्द्र सिंह भदौरिया तथा डबरा शाखा प्रबंधक प्रशांत रामपुरीया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऊर्जा संरक्षण एवं हरित सहकार अभियान को जनआंदोलन बनाएं : महेन्द्र सिंह यादव

भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की बैरसिया शाखा में सदस्यता महाअभियान एवं सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल। भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. भोपाल की शाखा बैरसिया में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव ने गुरुवार को भेंट कर सहकारिता गतिविधियों, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान एवं हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

भेंट के दौरान प्रशासक श्री यादव ने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए "ईंधन बचाओ – ऊर्जा बचाओ" के आह्वान को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण के प्रति सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही "वोकल फॉर लोकल" अभियान को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया।

प्रशासक श्री यादव ने "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत बैंक मुख्यालय एवं पैक्स स्तर पर निर्धारित पौधरोपण लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि "हरित सहकार अभियान" केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन एवं ग्रामीण विकास की दिशा में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक ग्रामीणों एवं किसानों को इस अभियान से जोड़ने का आह्वान किया।

इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घोषित "कृषक कल्याण वर्ष-2026" के अंतर्गत 14 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक संचालित सदस्यता महाअभियान की भी समीक्षा की गई। प्रशासक श्री यादव ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा में अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

भेंट के दौरान प्रशासक श्री यादव ने किसानों से भी संवाद स्थापित किया तथा ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था एवं अन्य बैंकिंग सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बी-पैक्स संस्थाओं की वार्षिक आमसभा में चयनित सदस्य किसानों को सम्मानित किए जाने का सुझाव भी दिया, ताकि किसानों में सहकारिता के प्रति विश्वास और सहभागिता बढ़ सके।

कार्यक्रम के दौरान प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अभय प्रधान, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गीतेश लिल्होरे, विपणन अधिकारी निमेष शाही तथा शाखा प्रबंधक समीउल्लाह कुरैशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भेंट एवं समीक्षा के दौरान यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि सहकारिता केवल वित्तीय सेवाओं का माध्यम नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक उत्थान, पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास का सशक्त आधार है। ऊर्जा संरक्षण, हरित अभियान एवं सदस्यता विस्तार जैसे प्रयास सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।